अपीलेट सिविल

माननीय न्यायालय राजेंद्र नाथ मित्तल, जे.

शेर सिंह,-अपीलार्थी

बनाम

मेहर सिंह ईटीसी.,-उत्तरदाता

नियमित दूसरी अपील सं 1969 का 1819

7 अप्रैल, 1972

पंजाब प्री-एम्पशन एक्ट (1913 का 1)-धारा 15 (1) (ए) उपखंड-द्वितीयक 'और 15 (2)-हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956 का XXX)-धारा 14-प्रथा के तहत विधवा की संपत्ति-प्रकृति-पति द्वारा छोड़े गए संपत्ति का पूर्ण मालिक बन जाता है या नहीं, उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के तहत संपत्ति का पूर्ण मालिक बन जाता है-ऐसी विधवा द्वारा बिक्री-पूर्व-छूट का अधिकार-धारा 15 (2) प्री-एम्पशन एक्ट-क्या लागू होता है।

माना जाता है कि प्रथा के तहत एक विधवा की संपत्ति हिंदू कानून के तहत एक विधवा के समान है। प्रथा के साथ-साथ हिंदू कानून के तहत, एक विधवा को केवल एक सीमित संपत्ति मिलती है जो उसकी मृत्यु पर उसके पति के अगले उत्तराधिकारियों को जाती है। जहां एक पति की मृत्यु हो जाती है, बिना किसी प्रतिवर्ती को छोड़े, तो उसकी विधवा उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति की पूर्ण स्वामी नहीं बन जाती है। प्रतिवर्ती की अनुपस्थिति में भी, उसे संपत्ति को अलग करने का कोई अधिकार नहीं है। वह राज्य जिसके पास संपत्ति है! एक विधवा के अलगाव को चुनौती देने का अधिकार है। इस प्रकार जहां कोई विधवा सीमित स्वामी के रूप में संपत्ति विरासत में प्राप्त करती है और ऐसी संपत्ति की बिक्री के विरुद्ध पूर्व-छूट के वाद में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 के आधार पर पूर्ण स्वामी बन जाती है, तो यह पंजाब पूर्व-छूट अधिनियम, 1913 की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (ए) का उपखंड 'द्वितीयक' है, जो लागू होता है और नहीं) इसकी धारा 15 का उपखंड (2)। (Paras 4, 15 and 18).

श्री एस. आर. सेठ, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कमल की 2 अगस्त, 1969 की अदालत की डिक्री से नियमित दूसरी अपील, जिसमें श्री राम कुमार गुप्ता) उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, कमल, दिनांक 7 फरवरी, 1969 की लागत की पुष्टि की गई है, जिसमें वाद में 1617.50 रुपये के भुगतान पर वाद में संपत्ति के कब्जे के लिए वादी की डिक्री को मंजूरी दी गई है, जिसमें विलेख व्यय और उक्त धन जो पहले से जमा है, को प्रतिवादी नं. 2 10 मार्च, 1969 को या उससे पहले, अन्यथा वाद खारिज हो जाएगा और पक्षकारों को अपना खर्च वहन करना होगा।

अपीलार्थी की ओर से वकील के. एस. थापर और मिस. सुरजीत कौर टौंक।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता एम. एस. जैन।

अदालत का फैसला

1) यह अपील अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल, दिनांक 2 अगस्त, 1969 के फैसले और डिक्री के खिलाफ दायर की गई है, जिसके द्वारा 1,500 रुपये के भुगतान पर पूर्व-आवेदन द्वारा कब्जा करने के डिक्री के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है।

2) संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि विवादित बारा को आसा सिंह की विधवा बिश्नी ने प्रतिवादी शेर सिंह को रुपये में बेच दिया था। 1, 500,-18 मई, 1967 का विक्रय विलेख, 19 मई, 1967 को पंजीकृत। मेहर सिंह वादी ने इस आधार पर कब्जा के लिए मुकदमा दायर किया कि वह विक्रेता के भाई का बेटा था। हालाँकि, उन्होंने आरोप लगाया कि वास्तव में रु। 500 का भुगतान वास्तव में बारा के रूप में किया जाता था और यह उसका बाजार मूल्य भी था। प्री-एम्प्टर से बचने के लिए, रुपये के रूप में विचार किया गया है। 1, 500 बिक्री विलेख में। प्रतिवादी-विक्रेता ने वाद का विरोध किया और वादी के अधिमान्य अधिकार से इनकार किया और कहा कि विक्रेता को उसके पति से संपत्ति विरासत में मिली थी और इसलिए, वादी को पूर्व-मुक्ति का कोई बेहतर अधिकार नहीं था। कीमत के बारे में उन्होंने कहा कि रु। 1, 500 अच्छे विश्वास में तय किए गए थे और वास्तव में भुगतान किया गया था। पक्षकारों की दलीलों पर, निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थेः-"(1) क्या वादी को पूर्व-मुक्ति का उच्चतर अधिकार है?
(2) क्या बिक्री मूल्य वास्तव में भुगतान किया गया था और या सद्भावना से तय किया गया था?
(3) यदि मुद्दा नं। 2 साबित नहीं हुआ है, बिक्री के समय सूट में जमीन का बाजार मूल्य क्या था?
(4) क्या सूट में बिक्री पूर्व-खाली नहीं है?
(5) क्या विक्रेता विलेख व्यय के हकदार हैं?
(6) राहत।"

3) ट्रायल कोर्ट ने वादी के पक्ष में नंबर 1 जारी करने और प्रतिवादी के खिलाफ नंबर 4 जारी करने का फैसला किया। निर्गम संख्या 2,3 और 5 पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1,500 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था जो संपत्ति का बाजार मूल्य भी था। प्रतिवादी को बिक्री विलेख के खर्च की भी अनुमति दी गई थी। उपर्युक्त परिस्थितियों में, मुकदमा निचली अदालत द्वारा तय किया गया था। विद्वत अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि की और अपील को खारिज कर दिया। प्रतिवादी-विक्रेता इस अदालत में अपील करने आया है।

4) विक्रेता के विद्वान वकील द्वारा जो एकमात्र तर्क उठाया गया है, वह यह है कि विक्रेता को संपत्ति उसके पति से मिली थी, जिसने कोई प्रतिवर्ती नहीं छोड़ा था। उनके द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया कि विक्रेता का पति प्रथागत कानून द्वारा शासित था। प्रथा के अनुसार यदि कोई पुरुष बिना किसी प्रत्यावर्तक के मर जाता है, तो विधवा को संपत्ति एक सीमित मालिक के रूप में नहीं बल्कि एक पूर्ण मालिक के रूप में मिलती है। वह प्रस्तुत करता है कि वर्तमान मामले में अंतिम पुरुष धारक आसा सिंह की बिना किसी प्रत्यावर्तक के मृत्यु हो गई, श्रीमती बिश्नी को उनकी संपत्ति पूर्ण मालिक के रूप में विरासत में मिली। इससे वह यह अनुमान लगाता है कि वर्तमान मामले में छूट का अधिकार पंजाब छूट अधिनियम, 1913 की धारा 15 (2) (बी) में दिए गए व्यक्तियों में निहित है (जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) दूसरी ओर, वादी-प्रत्यर्थी का विद्वत वकील प्रस्तुत करता है कि विक्रेता को एक सीमित स्वामी के रूप में संपत्ति विरासत में मिली और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (इसके बाद 'उत्तराधिकार अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के लागू होने पर वह इसकी धारा 14 के आधार पर पूर्ण स्वामी बन गई। यदि वह संपत्ति की पूर्ण स्वामी थी, तो प्रत्यर्थी संख्या 1 अधिनियम

की धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के उपखंड 'द्वितीयक' के तहत बिक्री को पूर्व-खाली करने का हकदार था। वह आगे प्रस्तुत करता है कि उसे केवल सीमित संपत्ति विरासत में मिली थी और उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के आधार पर संपत्ति के विस्तार पर, वह संपत्ति की पूर्ण स्वामी बन जाएगी और उस मामले में, अधिनियम की धारा 15 का उपखंड (2) उसकी संपत्ति पर लागू नहीं होगा। श्री के. एस. थापर स्वीकार करते हैं कि यदि यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विधवा को उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 द्वारा विस्तारित सीमित संपत्ति विरासत में मिली थी, तो वादी-प्रत्यर्थी को पूर्व-मुक्ति का उच्चतर अधिकार प्राप्त है। उनका एकमात्र तर्क यह है कि उन्हें अपने पति से पूरी संपत्ति विरासत में मिली थी। उस मामले में, धारा 15 की उपधारा (1) लागू नहीं होगी। इससे पहले कि मैं विभिन्न अधिकारियों का उल्लेख करूं, जिनका पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा उल्लेख किया गया था, यह फायदेमंद होगा यदि पक्षकारों के आरोपों को पक्षकारों की दलीलों से देखा जाए। पैरा 1 में, वादी का कहना है कि प्रतिवादी नंबर 1 विवाद में बारा का मालिक था और उसके कब्जे में था। वादपत्र के पैरा 3 में, वादी अपने पूर्व-मुक्ति के उच्चतर अधिकार के बारे में बताता है जो निम्नलिखित शर्तों में हैः " कि वादी विक्रेता-प्रतिवादी नंबर 1 का असली भाई का बेटा है जबकि विक्रेता किसी भी तरह से विक्रेता से संबंधित नहीं है और एक अजनबी है। इसलिए वादी के पास प्रतिशोधक-प्रतिवादी के लिए पूर्व-मुक्ति का बेहतर अधिकार है।"

5) लिखित बयान में, प्रतिवादी नंबर 2, एक प्रारंभिक आपत्ति उठाता है जो निम्नलिखित शब्दों में हैः-"यह पूर्व-छूट के लिए मुकदमा है क्योंकि विक्रेता श्रीमती बिश्नी को अपने पति से विरासत में बारा मिला था।"

6) पैरा नम्बर 1 के उत्तर में प्रतिवादी 2 कहता है कि पैरा नम्बर 1 सही है। इसके अलावा, वह कहता है कि विक्रेता को अपने पति से अन्य भूमि के साथ बारा विरासत में मिला था। पैरा संख्या 3 के उत्तर में, वह केवल यह कहता है कि उक्त पैरा गलत है।

7) उपर्युक्त पैरा के पुनरुत्पादन से, यह देखा जाएगा कि विक्रेता-प्रत्यर्थी ने कभी भी किसी विशेष प्रथा के बारे में कोई दलील नहीं ली जो अब उसके द्वारा अपने तर्कों में ली गई है। यह बहस के समय ही है कि विक्रेता ने यह स्थिति ली कि विक्रेता को अपने पति से एक पूर्ण मालिक के रूप में संपत्ति विरासत में मिली है। इसके समर्थन में, वह सामान्य प्रथा पर निर्भर था न कि किसी विशेष प्रथा पर। अब राज्य में सामान्य प्रथा का पता लगाने के लिए, मैं उन विभिन्न प्राधिकरणों पर चर्चा करना चाहता हूं जिनका बार में उल्लेख किया गया है।

8) श्री थापर ने मुख्य रूप से अलाइक और अन्य बनाम गौहरा और अन्य पर भरोसा किया है, जहां अंतिम पुरुष-धारक एक विधवा को छोड़कर निःसंतान मर गया जो उसकी संपत्ति में सफल हुई। विधवा की मृत्यु पर, उसके भाई के बेटे ने भूमि पर कब्जा कर लिया। जिसने विधवा द्वारा अपने पक्ष में वसीयत के तहत इसे रखने का दावा किया। साझेदारी के मालिकों ने अंतिम मालिक के संपार्श्विक के अभाव में संपत्ति के हकदार होने का दावा करते हुए कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर किया और वसीयत की वैधता को चुनौती दी। रैटिगन और स्कॉट-स्मिथ जे. जे. की विद्वत पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि वादी इस बात का प्रमाण नहीं दे सकते हैं कि पट्टी के मालिकों को अंतिम पुरुष-धारक की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार है। विधवा की संपत्ति के बारे में विचार करते हुए, विद्वत पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी कीः-"श्री. पेस्टनजी आग्रह करते हैं कि विधवा की संपत्ति हमेशा सीमित रहे। काफी हद तक, लेकिन यह केवल उलटने वालों के लाभ के लिए सीमित है। जहाँ कोई नहीं है वहाँ वह सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए एक पूर्ण मालिक है। वकील ने हमें वजीरा बनाम मंगल (2) का भी उल्लेख किया, लेकिन हमें वहां ऐसा कुछ नहीं मिला जो उनके तर्क से मेल खाता हो। वित्तीय आयुक्त द्वारा उसमें

निर्धारित 5वां प्रस्ताव उनके खिलाफ है। संक्षेप में, हम मानते हैं कि जिम्मेदारी मैदानों पर थी और उन्होंने इसे पूरा नहीं किया है। अपील विफल हो जाती है और लागत के साथ खारिज कर दी जाती है।"

9) अपीलार्थी के लिए विद्वत वकील मुख्य रूप से उपरोक्त टिप्पणियों पर अपना भरोसा रखता है, जिसका प्रभाव यह है कि यदि पति की मृत्यु के समय प्रत्यावर्तक अस्तित्व में नहीं हैं, तो वह सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए एक पूर्ण स्वामी है। इसके बाद, उक्त निर्णय के बाद न्यायमूर्ति शादी लाई, (जैसा कि उन्हें तब बताया गया था) को ज्ञानी राम और अन्य बनाम मुस्समत मारी और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें थुला के मालिकों और विधवा के बीच विवाद था और विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रकार टिप्पणी कीः-"निर्धारण का मुद्दा यह है कि क्या थुला में मालिकों को अपने पति के लिए एक बेटे को गोद लेने की विधवा की शक्ति का विरोध करने का कोई अधिकार है। अब अल्लाह डिट्टा बनाम गौहरा (ऊपर) में यह निर्धारित किया गया है कि पट्टी के मालिकों पर एक विधवा द्वारा अलगाव का विरोध करने के अपने अधिकार को स्थापित करने की जिम्मेदारी है और यह कि एक विधवा की संपत्ति केवल प्रत्यावर्तकों के लाभ के लिए सीमित है, और जहां कोई नहीं है, वह सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए एक पूर्ण मालिक है।

10) उपर्युक्त दो मामलों में उपरोक्त टिप्पणियों से, अपीलार्थी का विद्वत वकील प्रस्तुत करता है कि जहां कोई अंतिम पुरुष मालिक किसी भी प्रत्यावर्तक को छोड़े बिना मर जाता है, विधवा को संपत्ति एक पूर्ण मालिक के रूप में विरासत में मिलती है। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा मेरे ध्यान में कोई अन्य मामला नहीं लाया गया है जहाँ इन मामलों का बाद में पालन किया गया है। दूसरी ओर, ऐसे अधिकारियों की एक कड़ी है जिन्होंने एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रथागत कानून के तहत विधवा को एक सीमित संपत्ति मिली है और उसे एक हिंदू विधवा के समान अधिकार मिले हैं। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में विभिन्न मामलों का हवाला दिया। पहला मामला जिस पर उन्होंने भरोसा किया, वह मास्टर दियाल कौर और अन्य बनाम मास्टर मेहताब कौर और अन्य (4) के रूप में रिपोर्ट किया गया है, जहां लाहौर उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी कीः-"एक विधवा जो सीमा शुल्क के तहत एक संपत्ति में जीवन हित रखती है, उसे हिंदू कानून के तहत समान संपत्ति रखने वाली विधवा की तुलना में अलगाव की कोई व्यापक शक्ति नहीं है।"
हिंदू कानून के तहत एक विधवा की शक्तियों पर चर्चा करते हुए, मसूली-पटम बनाम कवाली वेंकट नरानिनपाह के कलेक्टर पर भरोसा करने वाले उनके प्रभुओं ने कहा कि हिंदू कानून के तहत संपत्ति में विधवा के जीवन हित की सीमित प्रकृति कभी नहीं बदल सकती है, भले ही उत्तराधिकारियों की पूरी कमी हो और उसके पति की संपत्ति के अलगाव की शक्ति पर लगाए गए प्रतिबंध उसकी संपत्ति से अविभाज्य थे और उनका अस्तित्व उसकी मृत्यु को संभालने में सक्षम उत्तराधिकारियों पर निर्भर नहीं था। हालाँकि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि उपरोक्त मामले पर बहस करते समय अल्ला डिट के मामले को उनके लॉर्डशिप के ध्यान में नहीं लाया गया था। एक हिंदू विधवा के अधिकारों के संबंध में, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील मसूलीपट्टम के कलेक्टर बनाम कवाली वेंकट नारायणपाह पर निर्भर करता है, जहां यह देखा गया है कि एक निःसंतान विधवा केवल सीमित संपत्ति लेती है। उनके लॉर्डशिप्स ऑफ द प्रिवी काउंसल की टिप्पणियां इस प्रकार हैंः -

"विरासत के हिंदू कानून के अनुसार, एक निःसंतान विधवा उत्तराधिकारी के रूप में लेती है, लेकिन यह केवल एक विशेष और योग्य संपत्ति है।
यदि पति के संपार्श्विक उत्तराधिकारी हैं, तो विधवा विशेष उद्देश्यों के अलावा संपत्ति को अलग नहीं कर सकती है, जैसे कि धार्मिक या धर्मार्थ वस्तुओं के लिए, या उन कार्यों के लिए जो उसके पति के आध्यात्मिक कल्याण के लिए अपेक्षित हैं, उन परिस्थितियों में उसके पास स्वभाव की अधिक शक्ति है

जो उसके पास विशुद्ध रूप से सांसारिक उद्देश्यों के लिए है। बाद के उद्देश्य के लिए अलगाव का समर्थन करने के लिए, उसे वास्तविक आवश्यकता दिखानी चाहिए।
अपने पति की संपत्ति के अलगाव की विधवा की शक्ति पर हिंदू कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंध उसकी संपत्ति से अविभाज्य हैं और उसकी मृत्यु को संभालने में सक्षम उत्तराधिकारियों के अस्तित्व पर निर्भर नहीं करते हैं।
जब क्राउन उत्तराधिकारियों की कमी के कारण अलग से लेता है, तो उसे विधवा द्वारा अनधिकृत अलगाव का महाभियोग चलाने का वही अधिकार है, जो पति के उत्तराधिकारियों (यदि कोई होता) को होता।"

उपरोक्त मामले के अनुसार, यहां तक कि क्राउन जो एक विधवा की संपत्ति को धोखा देकर लेता है, उसे भी उसके अलगाव को चुनौती देने का अधिकार मिला है। तत्पश्चात तीरथ राम बनाम मुसम्मत काहन देवी के रूप में रिपोर्ट किए गए एक मामले में, उस न्यायालय की एक खंड पीठ ने कहा कि हिंदू कानून के अनुसार, एक विधवा की अलगाव की शक्तियां धार्मिक उद्देश्यों तक ही सीमित हैं, और यह तथ्य कि कोई भी उत्तराधिकारी उसकी मृत्यु को स्वीकार करने में सक्षम नहीं है, इन शक्तियों को प्रभावित नहीं करता है। अल्ला डिट्टा के मामले को विद्वत पीठ के समक्ष भेजा गया था और विद्वत पीठ की टिप्पणियां थीं कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें पक्षकार प्रथा पर भरोसा करते थे और वादी अपने द्वारा विश्वास किए गए रीति को स्थापित करने में विफल रहे। अतः उस मामले में निर्णय का वर्तमान मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। इसके बाद, मामला फिर से लाहौर उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के सामने आया, जिसमें शादी लाई, C.J., और मार्टीनो जे., गोबिंदा और एक अन्य बनाम नंदू और एक अन्य के रूप में रिपोर्ट किया गया था, जो कस्टम के तहत एक मामला था। मसुलीपट्टम के कलेक्टर के मामले और दियाल कौर के मामले को देखने के बाद उनके लॉर्डशिप्स ने पाया कि प्रथागत कानून के तहत एक विधवा की संपत्ति हिंदू कानून के तहत एक विधवा के समान प्रतिबंधों के अधीन है। उनके लॉर्डशिप्स ने आगे कहा कि जहां किसी मामले में कोई प्रथा लागू नहीं थी, वादी अपने व्यक्तिगत कानून पर वापस आ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि यह मामला कस्टम के तहत था और उनके लॉर्डशिप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कस्टम के तहत विधवा की एक सीमित संपत्ति थी, शादी लाई, C.J., जिन्होंने ज्ञानी राम के मामले में अल्ला डिट्टा के मामले का पालन किया, उसी दृष्टिकोण से नहीं चिपके। दूसरी ओर, उनके प्रभुओं ने दियाल कौर के मामले में बाद के दृष्टिकोण का पालन किया, जो अल्ला डिट्टा के मामले में निर्धारित किए गए प्रस्ताव के विपरीत था। बाद में, कुंदन और अन्य बनाम राज्य सचिव और एक अन्य (8) में फिर से लाहौर उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने एक समान प्रश्न पर विचार किया, जिसमें उपरोक्त सभी मामलों को ध्यान में रखा गया और श्रीमती दियाल कौर के मामले का पालन किया गया। अल्ला डिट्टा के मामले पर चर्चा करते समय, उनके प्रभुओं ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:-"हम इस अवलोकन को एक विचारशील घोषणा के रूप में पढ़ने में असमर्थ हैं जिसका उद्देश्य आधिकारिक होना है कि प्रथागत नियमों द्वारा शासित एक हिंदू विधवा एक पूर्ण मालिक है, जब उसके मृत पति ने कोई रिश्तेदार नहीं छोड़ा है, और यह कि उसकी स्थिति अनिवार्य रूप से उससे अलग है जो उसके व्यक्तिगत कानून के तहत होगी। यदि ऐसा होता, तो विद्वान न्यायाधीशों ने "सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए" शब्दों का उपयोग नहीं किया होता, और जाहिर है कि इरादे और उद्देश्य प्रत्येक विशेष मामले की विशेष परिस्थितियों के साथ भिन्न होने चाहिए। उदाहरण के लिए, वर्तमान मामले में क्राउन ने हस्तक्षेप किया है और वास्तव में एक एस्केट के अपने दावे के अनुसरण में कब्जे में है। अल्ला डिट्टा बनाम गौहरा में, प्रतियोगिता स्वयं विधवा के एक रिश्तेदार के बीच थी, जिसने उसकी मृत्यु के बाद कब्जा हासिल कर लिया था और गाँव के मालिक जो प्रत्यावर्तन के लिए कोई खिताब साबित करने में विफल रहे थे। क्राउन द्वारा किए गए दावे के प्रभाव पर कभी दूर से विचार नहीं किया गया था।

इसके अलावा, इस न्यायालय की खंड पीठों द्वारा इसके विपरीत अन्य आदेश भी दिए गए हैं। एक दलीपा और अन्य में है, 'जहां तक हम जानते हैं कि यह कभी नहीं कहा गया है कि एक संपत्ति में जीवन ब्याज जो एक विधवा को सीमा शुल्क अनुदान देता है, किसी भी तरह से उस ब्याज से व्यापक है जो वह हिंदू कानून के तहत लेती है'।

दूसरा मुसम्मत दियाल कौर बनाम मुसम्मत मेहताब कौर में है, 'यह मानने का कोई आधार नहीं है कि एक विधवा जो प्रथा के तहत एक संपत्ति में जीवन हित रखती है, उसे हिंदू कानून के तहत समान संपत्ति रखने वाली विधवा की तुलना में अलगाव की कोई व्यापक शक्तियां हैं।'

तीसरा गोविंद बनाम नंदू में दिया गया था, जिसमें मुसम्मत दियाल कौर बनाम मुसम्मत मेहताब कौर से ऊपर उद्धृत की गई बात की स्वीकृति व्यक्त की गई थी, और रिपोर्ट के मुख्य टिप्पण में कहा गया है कि न्यायाधीशों ने यह निर्धारित किया है कि प्रथागत कानून के तहत एक विधवा की संपत्ति हिंदू कानून के तहत एक विधवा के समान प्रतिबंधों के अधीन है।

हमें इन टिप्पणियों की अवहेलना करने के लिए कहा गया है क्योंकि तीनों मामलों में से प्रत्येक एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां अंतिम पुरुष मालिक ने महिलाओं के माध्यम से महिला रिश्तेदारों या पुरुष रिश्तेदारों को पीछे छोड़ दिया था, जो हिंदू कानून के तहत बंधुओं के रूप में सफल होने के हकदार होते। हम पर यह दबाव डाला जाता है कि टिप्पणियां अनिवार्य रूप से उन विशेष मामलों के तथ्यों से प्रेरित रही होंगी जिनसे न्यायाधीश निपट रहे थे। अगर हमें इस दृष्टिकोण को अपनाना है, तो ठीक यही आलोचना श्री शेओ नारायण के अपने मामले अल्लाह डिट्टा बनाम गौहरा पर लागू होती है, और यह भी बाहर जाना चाहिए।"

11) अंत में न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि पंजाब में प्राकृतिक हिंदू विधवा की संपत्ति का निर्धारण इस आधार पर किया जाना है कि न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य संबंधित पक्षों पर लागू होने वाली प्रथा साबित होता है। यदि किसी प्रथागत नियम का कोई प्रमाण नहीं था, तो प्रश्न का निर्णय हिंदू कानून के अनुसार किया जाना था, बशर्ते उस कानून के किसी भी संशोधन को प्रथा द्वारा साबित किया जा सके। इस मामले की परिस्थितियों में, जो दृष्टिकोण लिया गया था, वह अल्लाह डिट्टा के मामले की तुलना में एक विपरीत दृष्टिकोण था, और यह भी देखा गया कि "सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए" शब्द प्रत्येक विशेष मामले की विशेष परिस्थितियों के साथ भिन्न होते हैं। अगला मामला जिसका संदर्भ दिया गया था वह इमाम दीन बनाम खामंदी और अन्य है। अल्लाह दीत्ता के मामले को फिर से विद्वान न्यायाधीश के समक्ष भेजा गया और अल्लाह दीत्ता के मामले और कुंदन के मामले को ध्यान में रखने के बाद, उनका प्रभुता इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रथा के तहत एक विधवा के पास केवल एक जीवन संपत्ति है और जीवन संपत्ति रखने वाली विधवा द्वारा अलगाव के मामले में, यह पूरी तरह से मायने नहीं रखता था कि अगला उत्तराधिकारी पुरुष संपार्श्विक है या महिला। अल्लाह डिट्टा के मामले के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश की टिप्पणियां यह हैं कि कुंदन और अन्य बनाम राज्य सचिव और एक अन्य (उपर्युक्त) में उस उक्ति का पालन नहीं किया गया था और यह स्पष्ट था कि इसे बहुत व्यापक शब्दों में कहा गया था। एम. मोहम्मद में फिर से। शरीफ और अन्य बनाम तेजा सिंह और अन्य बनाम कोल्डस्ट्रीम, जे., जिनके साथ न्यायमूर्ति जय लाई ने सहमति व्यक्त कीः-"इस न्यायालय द्वारा अक्सर यह देखा गया है कि प्रांत के प्रथागत कानून के तहत विधवा की शक्तियां हिंदू कानून द्वारा शासित विधवा की शक्तियों के समान हैं।

12) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तब सैयद खादम हुसैन और अन्य बनाम सैयद मोहम्मद हुसैन और एक अन्य का उल्लेख किया, जहां लगभग सभी उपरोक्त मामलों को भिडे और दीन मोहम्मद जेजे की लाहौर उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा विचार में लिया गया था। मामला कानून पर विचार करने के बाद, उनके स्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रथागत कानून के तहत विधवाओं की शक्तियां सीमित थीं। उनके लॉर्डशिप्स ने अल्लाह डिट्टा के मामले को भी ध्यान में रखा और निम्नलिखित टिप्पणियां कींः-

"उत्तरदाताओं के लिए इन अधिकारियों के वकील अल्लाह डिट्टा बनाम गौहरा का उल्लेख करते हैं, जहां रैटिगन और स्कॉट 4 स्मिथ, जे. जे. ने यह स्वीकार करते हुए कि एक विधवा की संपत्ति हमेशा सीमित होती है, कहा कि यह केवल वापसी करने वालों के लाभ के लिए सीमित है और जहां कोई नहीं है, वह सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए एक पूर्ण मालिक है। लेकिन इस तथ्य के अलावा कि वर्तमान मामले में उलटने वाले अस्तित्व में हैं और परिणामस्वरूप यह निर्णय कोई बल नहीं है, इसे तीरथ राम बनाम मुसम्मत काहन देवी में अलग किया गया था। यह आधार कि वहां के वादी उस प्रथा को स्थापित करने में विफल रहे थे जिस पर वे निर्भर थे। इसी तरह, कुंदन और अन्य बनाम राज्य सचिव और एक अन्य मामले में, एफोर्ड और कैंपबेल जे. जे. से बनी इस अदालत की एक खंड पीठ ने ऊपर पुनः प्रस्तुत की गई उक्ति को मंजूरी नहीं दी और इसे केवल आज्ञाकारी माना। इमाम दीन बनाम खामंदी में। एडिसन जे., एफोर्ड और कैम्पबेल जे. जे. के विचार अल्लाह डिट्टा बनाम गौहरा से सहमत थे। इसके अलावा, इस प्रस्ताव के समर्थन में पर्याप्त अधिकार है कि प्रथागत कानून के तहत एक विधवा को हिंदू कानून के तहत विधवा के समान दर्जा प्राप्त है।

13) न्यायाधीशों ने कुंदन के मामले में बाद के दृष्टिकोण का भी पालन किया। प्रथागत कानून के तहत अपने पति की संपत्ति में विधवाओं के अधिकारों के बारे में सवाल भी ए. यू. मोहम्मद बनाम माउंट में पांच माननीय न्यायाधीशों की एक पूर्ण पीठ के समक्ष विचार के लिए आया। मुगलानी और अन्य। उस मामले में उनके प्रभुओं ने फिर से वही दृष्टिकोण अपनाया कि विधवा के पास संपत्ति में सीमित संपत्ति थी और सैयद खादम हुसैन के मामले को मंजूरी दी। उनके प्रभुता का अवलोकन इस प्रकार किया गयाः "पंजाब के प्रथागत कानून के तहत एक विधवा की संपत्ति हिंदू कानून के तहत विधवा के समान है। दोनों कानूनों के तहत वह स्वभाव की कुछ शक्तियों के साथ रखरखाव के उद्देश्य से जीवन भर के लिए रखती है जो उसके पद के लिए आवश्यक रूप से प्रासंगिक हैं। कम से कम प्रथागत कानून के तहत, वह किसी भी अर्थ में एक सहयोगी नहीं है, और उसकी मृत्यु पर उत्तराधिकार उसके लिए नहीं बल्कि उसके पति के लिए है। वास्तव में, उसकी संपत्ति केवल उसके पति और अगले उत्तराधिकारी के बीच एक सीमित उद्देश्य के लिए निहित है।

14) इसके बाद, न्यायाधीशों ने कहा कि एक हिंदू विधवा को पंजाब प्रथागत कानून के तहत विधवा की तुलना में संपत्ति के आनंद के मामले में अधिक अधिकार प्राप्त हैं। इस पूर्ण पीठ के निर्णय के बाद तीन माननीय न्यायाधीशों की एक और पूर्ण पीठ ने रबीदत बनाम माउंट। जवाब दीजिए। इस मामले में भी, उनके प्रभुओं ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन कियाः-"ऐसे मामलों में जहां प्रथा में अंतर है, ऐसे अंतर को पक्षों के व्यक्तिगत कानून के संदर्भ में भरा जाना चाहिए। विधवाओं द्वारा उपहार के विषय पर कोई प्रथा नहीं होने के कारण या तो सरल या धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए, विषयों को नियंत्रित करने वाले हिंदू कानून के सिद्धांतों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। पंजाब के प्रथागत कानून के तहत एक विधवा की स्थिति और उसके कार्यकाल की प्रकृति और घटनाएं हिंदू कानून के तहत होने वाली घटनाओं के बिल्कुल समान हैं।"

15) उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा, यह स्पष्ट है कि न्यायालयों का यह सुसंगत दृष्टिकोण रहा है कि प्रथा के तहत विधवा की संपत्ति हिंदू कानून के तहत विधवा के समान है। यह भी स्पष्ट है कि प्रथा के साथ-साथ हिंदू कानून के तहत, विधवा को केवल एक सीमित संपत्ति मिली है जो उसकी मृत्यु पर अगले उत्तराधिकारियों को दी जानी चाहिए। प्रतिवर्ती की अनुपस्थिति में भी, उसे संपत्ति को अलग करने का कोई अधिकार नहीं है। यहां तक कि जिस राज्य में संपत्ति अवैध रूप से जाती है, उसे भी विधवा के अलगाव को चुनौती देने का अधिकार है श्री थापर इन मामलों में अंतर करना चाहते थे और उन्होंने कहा कि अल्लाह डिट्टा के मामले में लिया गया दृष्टिकोण ही एकमात्र सही दृष्टिकोण था और प्रथा के तहत

विधवा, जिसके पास कोई प्रतिवर्ती नहीं था, संपत्ति का पूर्ण मालिक था। मैं उनके तर्क की सराहना करने में असमर्थ हूं। मैं, बहुत सम्मान के साथ, उस दृष्टिकोण से सहमत हूं जो प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत अधिकारियों में व्यक्त किया गया है।

16) अपीलार्थी का लिखित कथन भी किसी विशेष प्रथा का समर्थन नहीं करता है। यहां तक कि कोई विशेष प्रथा भी साबित नहीं हुई है कि करनाल जिले में एक विधवा के मामले में, उसे एक पूर्ण मालिक के रूप में संपत्ति मिलती है। उपर्युक्त परिस्थितियों में, मेरे लिए यह मानना भी संभव नहीं है कि उक्त जिले में एक विशेष प्रथा है जिसके द्वारा विधवा को अपने पति की मृत्यु पर संपत्ति में पूर्ण अधिकार मिलता है जब वह कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ता है।

17) अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि मसूली-पाटम के मामले (उपर्युक्त) के कलेक्टर की टिप्पणियाँ बहुत व्यापक रूप से लिखी गई हैं और वास्तव में हिंदू विधवा के अधिकार भी बहुत व्यापक हैं। उस मामले का पंजाब में भी अनुसरण किया गया है और आज तक इसे सही कानून माना गया है। इन परिस्थितियों में, मैं अपीलार्थी के विद्वान वकील के इस निवेदन से भी सहमत नहीं हूं। यह एकमात्र बिंदु था जिस पर मेरे सामने जोर दिया गया था।

18) ऊपर बताई गई परिस्थितियों में, अधिनियम की धारा 15 का उपखंड (2) वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है और वादी-प्रत्यर्थी को पूर्व-छूट का बेहतर अधिकार प्राप्त है। इसलिए यह अपील विफल हो जाती है और लागत के साथ खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कार्तिक शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

नूह, हरियाणा